आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शनिवार 04.01.2025
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया, कहा– गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की प्राथमिकता।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ग्लेशियर झीलों के विस्तृत अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए कार्ययोजना तैयार कर रहा है।
- प्रदेश सरकार ने इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3 हजार 100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा।
- उत्तराखंड को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में सम्मानित किया गया।

ग्रामीण भारत महोत्सव 2025

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव के लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य भारत के गांव के लोगों सशक्त बनाकर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर देना है।

श्री मोदी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए बहुत आवश्यक है कि गांव के हर वर्ग के लिए विशेष नीतियां बनाई हैं।

ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्देश्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण और ग्रामीण समुदायों में नवाचार को बढावा देना है। इस महोत्सव में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। 6 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए एक सुदृढ़ ग्रामीण भारत का निर्माण करना।

कार्ययोजना

उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) राज्य में स्थित ग्लेशियर झीलों के विस्तृत अध्ययन और उनकी नियमित निगरानी के लिए एक कार्ययोजना तैयार कर रहा है। यूएसडीएमए इन झीलों पर काम कर रहे विभिन्न शोध संस्थानों को सहयोग प्रदान करेगा। इस संबंध में कल सचिवालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय संस्थाओं के वैज्ञानिकों ने इस पर विचार–विमर्श किया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास सचिव, विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राज्य में 13 ग्लेशियर झीलें चिन्हित की गई हैं, जिनमें से पांच श्रेणी–ए में शामिल हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि चमोली जिले में स्थित वसुधारा झील का सर्वे किया जा चुका है, जबकि पिथौरागढ़ जिले की बाकी चार झीलों का सर्वे 2025 में किया जाएगा। इस अध्ययन में ग्लेशियर झीलों की गहराई, चौड़ाई, जल निकासी मार्ग और आयतन का अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद, इन झीलों की निगरानी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम और अन्य उपकरण स्थापित किए जाएंगे, जो इनके स्वरूप में होने वाले बदलावों का पता लगाने में मदद करेंगे।

स्थानीय उत्पाद

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थानीय उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि यह कदम न केवल राज्य के पारंपरिक कारीगरों और उत्पादकों को आर्थिक समर्थन प्रदान करेगा, बल्कि उत्तराखंड के अनूठे हस्तशिल्प और उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देकर उत्तराखंड की संस्कृति और परंपरा को जीवित रखना, प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। मुनस्यारी के ट्वीड जैसे उत्पाद राज्य की समृद्ध विरासत का प्रतीक हैं। सरकार हर संभव प्रयास करेगी कि स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से राज्य में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, इस पहल से राज्य के पर्यटन क्षेत्र को भी फायदा होगा, क्योंकि स्थानीय उत्पाद पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपेक्षा की है कि वे स्थानीय उत्पाद का उपयोग करें और कपड़े व स्थानीय ऊन से तैयार वस्त्रों को पहन कर इस अभियान को बढ़ावा दें। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री, मलारी और मुनस्यारी सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में ट्वीड से बनी जैकेट और मफलर पहनकर 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं। इस पहल को राज्य के स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उनकी ब्रांडिंग को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मंडुआ उत्पादन

प्रदेश सरकार ने इस साल विभिन्न सहकारी और किसान संघों के जरिए उत्तराखंड के किसानों से 3 हजार 100 मीट्रिक टन से अधिक मंडुआ खरीदा है। साथ ही इस साल किसानों को मंडुआ पर 4 हजार 200 प्रति कुंतल का समर्थन मूल्य भी दिया है। सहकारिता सचिव डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दूर–दराज के किसानों से मंडुआ खरीदने के लिए बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से जगह–जगह संग्रह केंद्र स्थापित किए। 2020–21 में जहां इन केंद्रों की कुल संख्या 23 थी, जो 2024–25 में बढ़कर 270 हो गई है। इन केंद्रों के जरिए इस साल प्रदेश के किसानों से करीब 3100 मीट्रिक टन मंडुआ की खरीद की गई, इसके लिए किसानों को 42 दशमलव 4–6 प्रति किलो की दर से समर्थन मूल्य दिया गया। सरकार ने मंडुआ खरीद में सहयोग देने के लिए किसान संघों को 150 रुपये प्रति कुंतल और बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को प्रति केंद्र 50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही सुनिश्चित किया गया कि केंद्रों का भुगतान 72 घंटे में कर दिया जाए।

सम्मान

उत्तराखंड को विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता के लिए शीर्ष उपलब्धियों की श्रेणी में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए उठाए गए विभिन्न पहलों के लिए दिया गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार की ओर से यह पुरस्कार उद्योग महानिदेशक प्रतीक जैन ने प्राप्त किया।

मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

प्रदेश में आम जनता को मतदान के प्रति जागरुक करने के लिये राज्य में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम सतत रूप से चलते रहेंगे। प्रत्येक माह इस प्रकार के थीम आधारित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, डॉ. बी. वी. आर. सी. पुरुषोत्तम ने कहा कि इन कार्यक्रमों की थीम इस तरह बनाई गई है, जिससे सभी वर्गों को इसमें जोड़ा जा सके। पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, देहरादून चौप्टर के प्रतिनिधियों ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और विशेष अभियान के तहत मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए चर्चा की। डॉ. पुरुषोत्तम ने कहा कि यह पहल मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने में मदद करेगी और समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करेगी।

निरीक्षण

चमोली के उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने आज राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की मौजूदगी में ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीनें डबल लॉक में सुरक्षित पाई गईं। उन्होंने वेयर हाउस में विद्युत व्यवस्था, सीसीटीवी कंट्रोल रूम और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया। वेयर हाउस में ईवीएम निरीक्षण करने के दौरान पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की गई।

केदारकांठा

उत्तरकाशी जिले में मोरी विकासखंड के अंतर्गत केदारकांठा में देश के विभिन्न राज्यों से ट्रैकर और पर्यटकों पहुंच रहे है। बर्फबारी के बाद केदारकांठा के बेस कैंप सांकरी में पिछले एक हफ्ते में 500 से ज्यादा पर्यटक पहुंचे हैं। यहां पहुंच रहे पर्यटक जहां केदारकांठा की नैसर्गिक सौंदर्य से खासा उत्साहित हैं, वहीं, पर्यटकों और ट्रैकरों के पहुंचने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिले हुए हैं।

वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम

केंद्र सरकार ने डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। मसौदा नियमों में बच्चों के सोशल मीडिया आकउंट खोलने के लिए अभिभावकों की अनिवार्य और प्रमाणित सहमति लेने का प्रावधान किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि मसौदा नियम परामर्श के लिए खुले हैं। उन्होंने लोगों से अपने विचार व्यक्त करने को भी कहा है। डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अगस्त 2023 में मंजूरी दी थी।

कृषि मंत्री बैठक

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को होने वाले नुकसान और फसल बीमा के माध्यम से मिलने वाले मुआवजे के बीच के अंतर को कम करने के लिए अब उपग्रहों के माध्यम से इन नुकसानों का सर्वेक्षण किया जाएगा। श्री चौहान ने महाराष्ट्र के नासिक में यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि जब प्याज या अन्य फसलों के दाम बढ़ने से लोगों की शिकायतें बढ़ती हैं, तो इसके कारण किसानों को मिलने वाली राशि में वृद्धि नहीं हो पाती है।

पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन

देहरादून में आगामी बारह जनवरी को पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 17 देशों से 50 से अधिक प्रवासी उत्तराखंडी इस भव्य सम्मेलन में भाग लेने के लिये पंजीकरण किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आयोजित इस कार्यक्रम में निवेश, कौशल विकास और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।